

अनुक्रमणिका

| क्र. सं. | टॉपिक का नाम |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 |
| 2. | राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 |
| 3. | राजस्थान शिक्षा विभाग की ज़िला एकेडमिक रैंकिंग (फरवरी, 2026) |
| 4. | न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. इंस्पायर अवार्ड के तहत राजस्थान के 5720 इनोवेटिव आइडिया चयनित 2. राजस्थान में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) 3. 55वाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह 4. ITB बर्लिन 2025 में राजस्थान |
| 5. | सी. वी. रमन (1888-1970) |
| 6. | भारत के पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन |
| 7. | हिंद महासागर में प्रमुख जलडमरूमध्य |
| 8. | चालू खाता घाटा |
| 9. | डूरंड रेखा |
| 10. | सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) |
| 11. | कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संपन्न |
| 12. | पश्चिम एशिया में हुए युद्ध के भारत पर प्रभाव |
| 13. | भारत-जापान द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था |
| 14. | अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) |
| 15. | फूड फोर्टिफिकेशन |
| 16. | वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) |
| 17. | ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) |
| 18. | आर्टेमिस कार्यक्रम |



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026



चर्चा में क्यों?

- राजस्थान विधानसभा द्वारा 5 मार्च, 2026 को राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- मुख्य उद्देश्य** : राज्य के विभिन्न कानूनों में छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा के प्रावधान को खत्म कर उन्हें केवल आर्थिक जुर्माने तक सीमित करना। साथ ही, यह विधेयक राज्य में 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देगा।
- इस विधेयक के माध्यम से राज्य के 11 अधिनियमों के तहत छोटे और तकनीकी उल्लंघनों के लिए कारावास की सजा को समाप्त किया गया है।
- जैसे** - राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 के तहत बिना लाईसेंस भंडारण किए जाने पर पूर्व में एक साल तक का कारावास और ₹1000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। इसमें संशोधन करते हुए अब कारावास को हटाकर शास्ति (जुर्माना) राशि को ₹50,000 तक बढ़ाया गया है।
- साथ ही, घरेलू पेयजल कनेक्शन के गैर-घरेलू उपयोग पर पहले एक वर्ष तक कारावास का प्रावधान था, जिसमें अब कारावास प्रावधान को हटाकर प्रतिदिन न्यूनतम ₹200 से अधिकतम ₹1,000 प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान वन अधिनियम-1953 की धारा 26 (1) (A) में वन भूमि में मवेशी चराने पर 6 माह तक कारावास या ₹500 तक जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान था। संशोधन के बाद उल्लंघन पर केवल जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान होगा।

--2--

Daily Current Affairs

Date : 06 March, 2026



विधेयक के माध्यम से संशोधित होने वाले अधिनियम:

| क्रम | अधिनियम का नाम |
|------|-------------------------------------------------|
| 1. | राजस्थान वन अधिनियम 1953 |
| 2. | राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 |
| 3. | राजस्थान नौचालन विनियम अधिनियम 1956 |
| 4. | राजस्थान भाण्डागार अधिनियम 1958 |
| 5. | राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम 1961 |
| 6. | राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1962 |
| 7. | राजस्थान साहूकार अधिनियम 1963 |
| 8. | राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 |
| 9. | राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 |
| 10. | राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 |
| 11. | जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम 2018 |

--3--

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान विधानसभा ने 5 मार्च, 2026 को राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित किया।

मुख्य बिन्दु:

- यह विधेयक मुख्य रूप से श्रमिकों के कार्य घंटों, ओवरटाइम और बाल श्रम निषेध से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव करता है।
- **संशोधन का उद्देश्य** : प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही श्रमिकों का कल्याण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रावधान :

- अध्यादेश में किए गए संशोधनों के अनुसार अब कम उम्र के बच्चों को दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में काम पर नहीं रखा जा सकेगा। प्रशिक्षु बनने की न्यूनतम आयु पहले 12 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 वर्ष कर दिया गया है।
- 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को रात्रि में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष तक थी।
- अध्यादेश में श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है। वहीं, ओवरटाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटों तक बढ़ाया गया है।
- साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है, साथ ही कम से कम आधा घंटा अंतराल के विश्राम से पहले कार्य करने की अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे किया गया है।

राजस्थान शिक्षा विभाग की ज़िला एकेडमिक रैंकिंग (फरवरी, 2026)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी, 2026 की ज़िला एकेडमिक रैंकिंग जारी की गई।

मुख्य बिन्दु:

ज़िला एकेडमिक रैंकिंग में शीर्ष तीन ज़िले :

| रैंक | ज़िले का नाम |
|-----------------|--------------|
| 1 st | करौली |
| 2 nd | झुंझुनूं |
| 3 rd | हनुमानगढ़ |

- रैंकिंग में बारों, उदयपुर और जोधपुर अंतिम पायदान पर रहे।
- यह रैंकिंग राजस्थान के समस्त ज़िलों के शैक्षणिक परिणामों, विद्यालयों के दैनिक संचालन और गवर्नेंस आदि संकेतकों में प्रदर्शन के आकलन के आधार पर जारी की जाती है।
- उद्देश्य :** जिलों के प्रदर्शन की नियमित, डेटा-आधारित समीक्षा करना और स्कूल शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही को सुदृढ़ करना।
- रैंकिंग में छात्रों की नियमित उपस्थिति, कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता, फील्ड विजिट के माध्यम से निगरानी और शैक्षणिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन जैसे प्रमुख मानकों को शामिल किया गया है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान की साक्षरता दर:

- कुल साक्षरता दर : 66.11 प्रतिशत।
- पुरुष साक्षरता : 79.19 प्रतिशत।
- महिला साक्षरता : 52.12 प्रतिशत।
- ग्रामीण साक्षरता : 61.4 प्रतिशत।
- शहरी साक्षरता : 79.7 प्रतिशत।

Daily Current Affairs

Date : 06 March, 2026



सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ज़िले:

| क्रम | ज़िला | साक्षरता दर (प्रतिशत में) |
|------|----------|---------------------------|
| 1. | कोटा | 76.6 |
| 2. | जयपुर | 75.5 |
| 3. | झुंझुनूं | 74.1 |
| 4. | सीकर | 71.9 |
| 5. | अलवर | 70.7 |

न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले:

| क्रम | ज़िला | साक्षरता दर (प्रतिशत में) |
|------|-----------|---------------------------|
| 1. | जालौर | 54.9 |
| 2. | सिरोही | 55.3 |
| 3. | प्रतापगढ़ | 56.0 |
| 4. | बाँसवाड़ा | 56.3 |
| 5. | बाड़मेर | 56.5 |

--6--



✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

| क्र. सं. | न्यूज़ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>इंस्पायर अवार्ड के तहत राजस्थान के 5720 इनोवेटिव आइडिया चयनित</p> <ul style="list-style-type: none">■ भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के 5,720 नन्हे वैज्ञानिकों के नवीन विचारों (इनोवेटिव आइडिया) का चयन किया गया है।■ शिक्षा सत्र 2025-26 के तहत राज्य से करीब 1.42 लाख अभ्यर्थियों ने अपने इनोवेटिव आइडिया ऑनलाइन अपडेट किए थे, जिसमें से 5720 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या जयपुर (557) के रहे।■ चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को अपना मॉडल या प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए ₹10,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते (DBT) में प्रदान की जाती है।■ यह योजना कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका उद्देश्य उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। |
| 2. | <p>राजस्थान में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)</p> <ul style="list-style-type: none">■ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना द्वारा राजस्थान के शाहजहांपुर, घीलोठ, नीमराणा, बहरोड़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों एवं प्रस्तावित KBNIR (Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana Investment Region) टाउनशिप को सीधे तौर पर दिल्ली और गुरुग्राम से उच्च गति रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास और आवागमन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। |

3.

55वाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह

- 55वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस (4 मार्च) का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA) स्थित बी.एस. मेहता ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।
- **मुख्य अतिथि** : उप-मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा।
- **आयोजक** : कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (राजस्थान स्टेट चैप्टर) द्वारा संयुक्त रूप से।
- **थीम** : "सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना"।
- **पुरस्कार वितरण** : कार्यक्रम में औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 औद्योगिक इकाइयों को 'कारखाना सुरक्षा पुरस्कार' प्रदान किए गए। ये पुरस्कार वृहद, मध्यम और लघु श्रेणियों में दिए गए।

4.

ITB बर्लिन 2025 में राजस्थान

- केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और जर्मनी में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते द्वारा ITB बर्लिन - 2025 में राजस्थान पर्यटन विभाग के पवेलियन का उद्घाटन किया गया।
- **प्रमुख आकर्षण** : राजस्थान पवेलियन (हॉल 5.2, स्टैंड 200) में नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025 का प्रदर्शन।
- विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार मेला ITB बर्लिन का आयोजन जर्मनी में 3 से 5 मार्च, 2026 तक किया गया।
- वर्ष 1966 से आयोजित हो रहा यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन विश्व पर्यटन उद्योग का अग्रणी मंच माना जाता है।



राष्ट्रीय परिदृश्य



सी. वी. रमन (1888-1970)



चर्चा में क्यों?

- भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध भौतिक-विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।



मुख्य बिन्दु:

सी. वी. रमन

- जन्म: तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)
- वैज्ञानिक योगदान
रमन प्रभाव की खोज (1928):
- रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) की वह परिघटना है जिसमें पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर पदार्थ में अणुओं की वजह से प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं और उनकी तरंगदैर्घ्य (रंग) में बदलाव आता है। इससे अणुओं की संरचना और कंपन के बारे में जानकारी मिलती है।
- अन्य प्रमुख योगदान: प्रकाशिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में योगदान, भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनिकी पर शोध, क्रिस्टलोग्राफी और ठोस अवस्था भौतिकी में शोध।
- पुरस्कार और सम्मान:
- रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार (1930), भारत रत्न (1954), रॉयल सोसाइटी के फेलो, फ्रैंकलिन पदक, लेनिन शांति पुरस्कार।

भारत के पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने साणंद (गुजरात) में भारत के पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र का विकास अमेरिकी निजी फर्म माइक्रोन ने किया है। यह संयंत्र सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग की सुविधा प्रदान करेगा।



मुख्य बिन्दु:

भारत के लिए महत्व

- **आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता:** इससे चिप्स के लिए विशेषकर चीन पर भारी आयात निर्भरता में कमी होगी। साथ ही, वैश्विक व्यवधानों (जैसे व्यापार युद्ध) के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होगी।
- **रणनीतिक महत्व:** रक्षा, दूरसंचार (5G/6G), AI, अंतरिक्ष और डिजिटल अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

- **आर्थिक और निर्यात वृद्धि:** इससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित होगा। इससे भारत को 2030 तक \$1 ट्रिलियन के सेमीकंडक्टर बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलेगी।
- **अन्य:** यह उच्च-कुशल रोजगार सृजित करेगा, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का समर्थन करेगा आदि।

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए शुरू की गई पहलें

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 1.0 और 2.0:** एक व्यापक सेमीकंडक्टर विनिर्माण तंत्र बनाने के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम।
- **ISM 2.0 (बजट 2026-27):** यह उपकरणों, सामग्रियों, फुल-स्टैक (शुरुआत से अंत तक संपूर्ण तंत्र) भारतीय बौद्धिक संपदा डिजाइन, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और कौशल विकास को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्स योजनाएं:** भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन और डिस्प्ले विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए राजकोषीय सहायता।
- **कंपाउंड सेमीकंडक्टर और ATMP/OSAT योजना:** घरेलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए चिप असेंबली, परीक्षण, पैकेजिंग और विशेषीकृत सेमीकंडक्टर खंडों (सेगमेंट्स) के लिए सहायता।
- **डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन (DLI) योजना:** स्वदेशी चिप डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स एवं MSMEs को प्रोत्साहन।
- **वैश्विक साझेदारी और कौशल पहल:** भारत-अमेरिका iCET सहयोग, सेमीकॉन इंडिया' प्लेटफॉर्म, तथा C2S एवं VLSI पाठ्यक्रम सुधार जैसे कार्यक्रम, ताकि कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके और निवेश आकर्षित किया जा सके।

भूगोल एवं भू-विज्ञान

हिंद महासागर में प्रमुख जलडमरूमध्य

चर्चा में क्यों?

- ईरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने का प्रयास करने वाले किसी भी जहाज़ पर वह हमला करेगा।



मुख्य बिन्दु:

जलडमरूमध्यों (Straits):

- अर्थ: यह प्राकृतिक रूप से बना संकरा जल मार्ग होता है। यह दो बड़े जल निकायों (समुद्र या महासागर) को जोड़ता है।

Daily Current Affairs

Date : 06 March, 2026



हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख जलडमरूमध्य:

- **होर्मुज जलडमरूमध्य:** यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- **बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य:** यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है।
- **मलक्का जलडमरूमध्य:** यह अंडमान सागर (हिंद महासागर) को दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) से जोड़ता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:13:-

आर्थिक घटनाक्रम

चालू खाता घाटा

चर्चा में क्यों?

- अप्रैल-दिसंबर 2025 की अवधि में चालू खाता घाटा (Current Account Deficit-CAD) कम होकर 30.1 अरब डॉलर रह गया। वहीं, एक वर्ष पहले समान अवधि में यह 36.6 अरब डॉलर था।



मुख्य बिन्दु:

CAD

- चालू खाता घाटा वह स्थिति है जब किसी देश द्वारा वस्तुओं, सेवाओं का कुल आयात और धन-अंतरण (ट्रांसफर), उसके कुल निर्यात और विदेश से अर्जित आय से अधिक हो जाता है।
- इसमें शामिल होते हैं: वस्तुएं और सेवाएं, विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त आय, तथा एकतरफा अंतरण जैसे प्रवासी द्वारा विप्रेषण (रेमिटेंस) और विदेशी सहायता।
- चालू खाता घाटा, व्यापक भुगतान संतुलन (Balance of Payments) का एक हिस्सा है।
- भुगतान संतुलन किसी देश का शेष विश्व के साथ होने वाले सभी वित्तीय लेन-देन को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

डूरंड रेखा

चर्चा में क्यों?

- पाकिस्तान ने डूरंड रेखा से सटे अफगानिस्तानी हिस्सों में 'ऑपरेशन गज़ब लिल-हक़' के तहत एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया।



मुख्य बिन्दु:

डूरंड रेखा

- यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगभग 2,600 किमी की सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। अफगानिस्तान इस सीमा को वैध नहीं मानता।
- डूरंड रेखा का प्रस्ताव ब्रिटिशों ने 1893 में दिया था, ताकि तत्कालीन ब्रिटिश-नियंत्रित भारत और अफगानिस्तान के बीच स्पष्ट विभाजन किया जा सके।
- इस सीमा रेखा का नाम सर मार्टिन डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे।

सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)

चर्चा में क्यों?

- यूरोपीय संघ और भारत ने पांच वर्षों की अवधि के लिए एक-दूसरे को 'सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र' (Most Favoured Nation-MFN) का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की है।



मुख्य बिन्दु:

सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)

- MFN सिद्धांत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का एक मूलभूत नियम है।
- इसके अनुसार, WTO का कोई सदस्य यदि किसी एक देश को कम शुल्क जैसी अनुकूल व्यापार शर्तें प्रदान करता है, तो वही लाभ उसे WTO के अन्य सभी सदस्यों को भी देना होगा।
- हालांकि, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, मुक्त व्यापार समझौतों और विकासशील देशों के लिए इसमें अपवाद मौजूद हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संपन्न

चर्चा में क्यों?

- भारत और कनाडा के संबंधों को 2018 में औपचारिक रूप से "रणनीतिक साझेदारी" का दर्जा दिया गया था।
- 2018 के बाद से यह किसी कनाडाई प्रधान मंत्री की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा थी।



मुख्य बिन्दु:

यात्रा के प्रमुख परिणाम

- **व्यापार समझौता:** 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (CEPA) के लिए 'विचारार्थ विषयों' (Terms of Reference - ToR) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** वर्तमान में दोनों देशों के बीच पण्य व्यापार लगभग 8-9 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए क्षमता से काफी कम है।

-:17:-

Daily Current Affairs

Date : 06 March, 2026



- **परमाणु ऊर्जा:** कनाडा की कंपनी कैमेको के साथ यूरेनियम अयस्क कॉन्सेंट्रेट्स की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक वाणिज्यिक अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया।
- **महत्वपूर्ण खनिज सहयोग:** सुरक्षित और लचीली खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **दाल प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र:** भारत और कनाडा के बीच एक 'संयुक्त दाल प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र' के लिए आशय की घोषणा की गई।

घोषणाएं

- **व्यापार लक्ष्य:** 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को \$50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- **वैश्विक गठबंधन:** कनाडा ने वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (GBA) और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन (ISA) में शामिल होने की घोषणा की।
- **संसदीय समूह:** भारत-कनाडा संसदीय मैत्री समूह का गठन किया जाएगा।
- **रक्षा संवाद:** भारत-कनाडा रक्षा संवाद की स्थापना की जाएगी।

-:18:-

पश्चिम एशिया में हुए युद्ध के भारत पर प्रभाव



चर्चा में क्यों?

- सरकार पश्चिम एशिया में हुए युद्ध के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। सरकार ने इसके आर्थिक परिणामों का आकलन करने के लिए निर्यातकों और लॉजिस्टिक क्षेत्र के अभिकर्ताओं के साथ अंतर-मंत्रालयी चर्चा की है।



मुख्य बिन्दु:

भारत पर पड़ने वाले प्रभाव

- ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा:** हॉर्मूज जलडमरूमध्य के बंद होने की आशंका बहुत चिंताजनक है, क्योंकि विश्व का लगभग 20% कच्चा तेल व्यापार यहीं से होता है।
- भारत की 85% LPG और 55% LNG हॉर्मूज जलडमरूमध्य से आती है।
- भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है।
- व्यापार पर प्रभाव:** भारत के लगभग 56% वस्तु निर्यात पर अनिश्चितता का खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह क्षेत्र भारत के लिए न केवल एक बड़ा बाजार है, बल्कि यूरोप और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा भी है।
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** पोत परिवहन मार्गों में बाधा आने से बीमा लागत और पारगमन समय बढ़ रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव खाड़ी देशों के जेबेल अली पत्तन (UAE) और सलालाह पत्तन (ओमान) जैसे प्रमुख ट्रांसशिपमेंट केंद्रों पर पड़ रहा है।
- प्रवासी:** खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों में कुल प्रवासी कामगारों में लगभग 30% हिस्सा भारतीयों का है।
- विप्रेषण:** RBI के विप्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत को मिलने वाले कुल विप्रेषण का लगभग 19% केवल UAE से और 7% सऊदी अरब से आता है। कुवैत, ओमान और कतर का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** इस संकट से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और भारत द्वारा संचालित चाबहार बंदरगाह के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

भारत-जापान द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

- भारत ने जापान के साथ अपनी द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (मुद्रा स्वैप समझौता) को नवीनीकृत किया है।



मुख्य बिन्दु:

- द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था दो-तरफा व्यवस्था है। इसमें दो देश अपनी-अपनी स्थानीय मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के बदले आपस में बदल सकते हैं।
- मुद्रा स्वैप (Currency Swap) का अर्थ है—दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच तय शर्तों के अनुसार एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा का लेन-देन करने का समझौता।
- भारत-जापान द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था की मात्रा: यह पहले की तरह 75 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- भारत द्वारा किए गए अन्य 'मुद्रा स्वैप समझौते (CSA)': सार्क मुद्रा स्वैप समझौता (2024-27), भारत-संयुक्त अरब अमीरात मुद्रा स्वैप समझौता, भारत-श्रीलंका मुद्रा स्वैप समझौता, आदि।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

चर्चा में क्यों?

- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल के सैन्य हमलों के प्रभावों पर चर्चा के लिए वियना में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की।

मुख्य बिन्दु:

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी:

- **स्थापना:** 1957
- **परिचय:** यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए विश्व का प्रमुख अंतर-सरकारी मंच है।
- **कार्य:** परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ावा मिल सके।
- **मुख्यालय:** वियना (ऑस्ट्रिया)
- **पुरस्कार:** वर्ष 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित।



⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

फूड फोर्टिफिकेशन

📢 चर्चा में क्यों?

- सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया।



📌 मुख्य बिन्दु:

- यह निर्णय IIT खड़गपुर के एक अध्ययन के बाद लिया गया है। अध्ययन में इस तथ्य पर जोर दिया गया कि नमी, भंडारण की स्थिति, तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता और पैकेजिंग सामग्री जैसे कारक 'फोर्टिफाइड राइस कर्नेल' (FRK) और 'फोर्टिफाइड राइस' (FR) की स्थिरता एवं शेल्फ-लाइफ को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

फूड फोर्टिफिकेशन

- यह खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए खाद्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे विटामिन और खनिज) की मात्रा को जानबूझकर बढ़ाने की प्रक्रिया है।

-:22:-

Daily Current Affairs

Date : 06 March, 2026



- **विनियमन:** FSSAI के खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2018 के तहत विनियमन किया जाता है।
- **PMGKAY और अन्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत वितरित होने वाले सभी कस्टम-मिल्ड चावल को मार्च 2024 तक फोर्टिफाइड चावल (FR) से बदल दिया गया था, जिसे दिसंबर 2028 तक वितरित किया जाना था।**

फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ:

- **गेहूं का आटा और चावल:** आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के साथ।
- **दूध और खाद्य तेल:** विटामिन A और D के साथ।
- **डबल फोर्टिफाइड नमक:** आयोडीन और आयरन के साथ।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:23:--

वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS)

चर्चा में क्यों?

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण किए।



मुख्य बिन्दु:

वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम

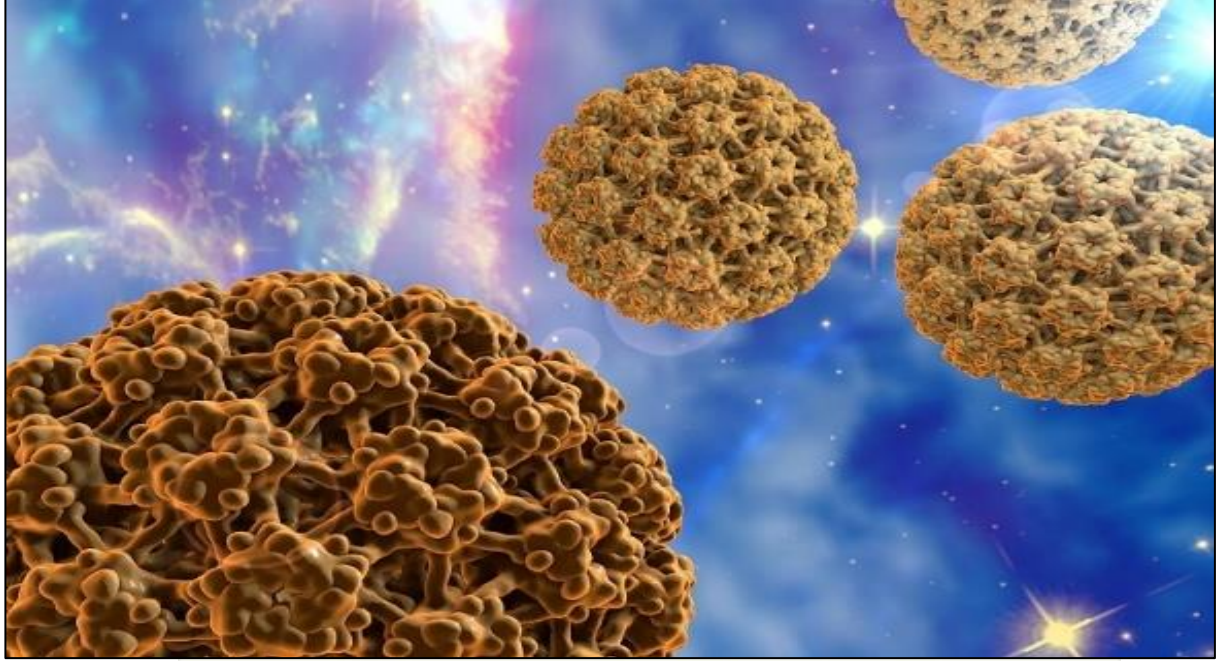
- VSHORADS मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS) है।
- **विकासकर्ता:** DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित।
- **क्षमता:** विभिन्न दूरी और अलग-अलग ऊंचाइयों पर उच्च गति वाले हवाई खतरों को अवरुद्ध करके नष्ट करने में सक्षम।
- **संचालनात्मक उपयोग:** भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल किया जाना है। स्तरित वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा।

ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV)



चर्चा में क्यों?

- प्रधान मंत्री ने 14 वर्षीय लड़कियों के लिए देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया।



मुख्य बिन्दु:

- इस कार्यक्रम में गार्डसिल-4 का उपयोग किया जा रहा है, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) को रोकने के लिए एक क्वाड्रिवैलेंट एकल-खुराक टीका है।
- गार्डसिल-4 लक्षित HPV प्रकारों के खिलाफ 93-100% प्रभावशीलता प्रदान करता है।
- एक 'क्वाड्रिवैलेंट' टीका चार अलग-अलग एंटीजन (जैसे- चार अलग-अलग विषाणुओं या सूक्ष्मजीवों) के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करके कार्य करता है।

ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV)

- **परिभाषा:** HPV 200 ज्ञात विषाणुओं के एक समूह का नाम है।
- **प्रसार:** यह एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण (STI) है।
- **प्रभाव:** अधिकांश लोगों में यह कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता, लेकिन उच्च जोखिम वाले HPV प्रकारों का लगातार संक्रमण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बनता है।
- 90% लोगों में शरीर स्वयं ही इस संक्रमण को नियंत्रित कर लेता है।

आर्टेमिस कार्यक्रम



चर्चा में क्यों?

- नासा आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम में बार-बार हो रही देरी के कारण इसका पुनर्गठन कर रहा है।



मुख्य बिन्दु:

आर्टेमिस कार्यक्रम:

- इसके तहत नासा चंद्रमा पर अधिक चुनौतीपूर्ण मानव मिशन भेजेगा। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक खोज और आर्थिक लाभ के लिए चंद्रमा का और अधिक अध्ययन करना है।
- आर्टेमिस-I को वर्ष 2022 में प्रक्षेपित किया गया था।
- आर्टेमिस-II, आर्टेमिस-III और आर्टेमिस-IV को भविष्य में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है।